पृष्ठ एक का शेष

वाराणसीके...

चितईपुर और टांस वरुणाके पुराने वार्डको लेकर २६ वार्डोंमें पेयजल और सीवर लाइन बिछानेका कार्य किया जायेगा। जिसमें करीब २६७८.९२ करोड़ खर्च होनेकी सम्भावना है। कैबिनेटसे इन प्रस्तावोंके स्वीकृत होनेके बाद संबंधित विभागोंने कागजी प्रक्रिया तेज कर दी। इन क्षेत्रोंमें टेण्डर आमंत्रित धरातलपर निर्माण कार्य शुरू कराये जायेंगे। जिससे नागरिकोंको गन्दगीसे मुक्ति मिलेगी। २२ वार्डोंमें अमृत दो योजनाके तहत २१६१ करोड़की लागतसे ३५३.१३ किलोमीटर सीवर लाइन और ६५१.६४ किलोमीटर पेयजल लाइन बिछानेको मंजूरी मिली है। जिन तीन वार्डोंमें ये लाइनें बिछायी जायेगी उनमें चितईपुरके अन्तर्गत भगवानपुर, छित्तूपुर खास, सीवरगोवर्धन, सुसुवाहीं, कंदवा और करौंदी। यहां के लिए कैबिनेटने पेयजल योजनापर २२७.९० करोड़, सीवर योजनापर ७४८.९० करोड़, इसी प्रकार लहरतारा जोनमें मंडुवाडीह, फुलवरिया, शिवदासपुर, लोहता, मढ़ौली, ककरमत्ताके लिए बजट स्वीकृत किया गया है जिसमें पेयजल योजनापर २१४.२१ करोड़, सीवर योजनापर ६३०.६४ करोड़ और वरुणा जोनमें पुराने वार्ड नम्बर १३ में सरसौली, तरना, पाण्डेयपुर, नारायणपुर, दनियालपुर, अकथा, सारनाथ, पहड़िया, खजुरी, रमरेपुर, ढिढोरी महाल, सिकरौल और शिवपुरमें पेयजल योजनापर २५२.८५ करोड़ और सीवर योजनापर ६०४.४२ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

104.28..

केंद्र (उप्र-सीएसओसी) की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस केंद्र के जरिये प्रदेश के डेटा सेंटर, उत्तर प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सरकारी ऐप्लीकेशन और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल परिसंपत्तियों की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि साइबर सुरक्षा से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि, हमले या डेटा सेंधमारी की स्थिति में त्वरित कारवाई और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने में यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रामलीला...

से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान की बुकिंग के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया था और अनुमति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, अशोक होटल में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने कहा कि यह निजी परिसर है और अनुमति का फैसला होटल प्रबंधन पर निर्भर करता है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए विपक्ष के अभियान में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर अपना अभियान जारी रखेगा। उनके मुताबिक, एक नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम में करीब 21 विपक्षी दल शामिल होंगे। जगह को लेकर अड़चन आने पर गठबंधन दूसरे स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करेगा।

ज्ञानेशके...

जवाब मांगे जाने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों और आम नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाएगा और जनता के वोट के अधिकार की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगा।

हटेंगे तीन...

गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों के तबादले के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि किसी अधिकारी को एक जिले में तीन साल से अधिक समय तक तैनात नहीं रखा जाए और गृह जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाए। निर्देशों के अनुसार, पिछले चार वर्षों में किसी जिले में तीन साल की सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों को भी स्थानांतरित करना होगा। गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में कार्यकाल की गणना के लिए 31 मार्च 2027 तथा उत्तर प्रदेश में 31 मई 2027 की कटऑफ तारीख तय की गई है। जिले के भीतर पदोन्नति के बाद की सेवा भी तीन साल की अवधि में शामिल होगी। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी और पुलिस उपनिरीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी को उस निर्वाचन क्षेत्र में तैनात न किया जाए, जहां वे पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए उपचुनाव के दौरान तैनात रहे हों। उल्लेखनीय है कि इन पांच राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च से मई 2027 के बीच समाप्त हो रहा है।

एमएलसी..

पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनाव में बेईमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने विधान परिषद चुनाव में बैलेट बॉक्स में बिना फोल्ड किये बैलेट मिलने का दावा करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाये। अखिलेश ने धर्मेंद्र कश्यप और उनकी बेटी कीर्ति कश्यप का सपा में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र कश्यप के आने से पीडीए का संघर्ष मजबूत होगा और भाजपा चुनाव हारेगी। अखिलेश ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची दुरुस्त कराने की अपील की। उन्होंने मतदान में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई। उनका आरोप था कि जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाता हैं, वहां लंबी कतारें लग रही हैं और केवल एक मशीन लगाकर मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि गोरखपुर में बिना सील का बाक्स मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि छोटी कारवाई के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।

सप्रीम कोर्टने...

आयोग में हो रही मीटिंग्स और कम्युनिकेशंस का ब्योरा सुरक्षित रखने का आदेश दे। इस पर ष्टछ्ठ सूर्यकांत ने कहा हमें सब पता है। हम जांच करेंगे। चुनाव आयोग ने सोमवार को ही कहा था कि स्ड्रक्र से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे। चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने स्ड्रक्र के फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया है। नियमों के अनुसार इस पर बदलाव का अधिकार केंद्र के पास है। फैसलों पर ष्टश्वष्ट ज्ञानेश कुमार, कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तीनों की सहमति थी। कोर्ट में दाखिल एफिडेविट पर भी तीनों के दस्तखत हैं।

निर्वाचन आयोग...

आयोग का यह तर्क 'भ्रामक' है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 26 सितम्बर, 2026 को निर्वाचन आयोग ने कहा था कि यह घोषणा पत्र फॉर्म-6 के साथ संलग्न है, जबकि अब उसका कहना है कि यह फॉर्म-6 का हिस्सा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग 'निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के खुले उल्लंघन' को छिपा नहीं सकता। रमेश ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) पर एसआईआर से जुड़े फैसले 'एकतरफा' तरीके से लेने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग अब यह दावा कर रहा है कि एसआईआर से जुड़े प्रमुख आदेशों को तीनों निर्वाचन आयुक्तों की औपचारिक मंजूरी प्राप्त थी। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि दो निर्वाचन आयुक्तों ने सीईसी के निर्देशों पर कथित उल्लंघनों और कार्रवाइयों को लेकर आधिकारिक रूप से आपत्ति दर्ज करायी थी, लेकिन उनकी आपत्तियों की अनदेखी की गयी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दोनों आयुक्तों को कुछ फैसलों की जानकारी समाचारों से मिली। रमेश ने कहा कि यह सर्वसम्मति नहीं, बल्कि एकतरफा निर्णय प्रक्रिया है। उन्होंने 'ईसीआईनेट' के जरिये मतदाता सूचियों पर नियंत्रण के कथित केंद्रीकरण को लेकर भी सवाल उठाये। रमेश ने दावा किया कि वैधानिक प्राधिकारी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के अधिकारों को दरकिनार किए जाने का मुद्दा दो निर्वाचन आयुक्तों ने रेकार्ड पर उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों से ईआरओ के फैसलों को कथित तौर पर पलटे जाने के मामले सामने आये हैं। रमेश ने निर्वाचन आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रभाग के कामकाज पर भी सवाल उठाते हुए दावा किया कि निर्वाचन आयुक्तों ने इसके 'अपारदर्शी' तरीके से काम करने, अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने और अनधिकृत कारवाई करने को लेकर बार-बार चिंता जतायी थी। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में अनेक कथित अनियमितताएं सामने आने का दावा करते हुए कहा कि कई राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का 'दुरुपयोग' किया गया। रमेश ने यह भी दावा किया कि आयोग के हलफनामे में मीडिया में सामने आयी कई जानकारियों की सत्यता से इनकार नहीं किया गया है और इसे उन्होंने कथित अनियमितताओं की पुष्टि बताया। कांग्रेस नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब हम छल करना शुरू करते हैं तो कितना उलझा हुआ जाल बुनते हैं। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया कानून के तहत अधिकृत है और इससे संबंधित आदेशों को आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी।

प्रतिभा और परिश्रम से संभावनाओं को उपलब्धियों में बदल रही युवाशक्ति-मुख्यमंत्री

लखनऊ (आससे.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उत्तर प्रदेश की युवाशक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम से संभावनाओं को उपलब्धियों में बदल रही है। उन्होंने वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार की बदली कार्य संस्कृति से भी प्रदेशवासियों को अवगत कराया और रोजगार सृजन में युवाशक्ति की नई पहचान भी बताई। मुख्यमंत्री ने लिखा कि नवाचार की नई सोच हो, उद्यमिता का साहस हो या विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के नए प्रतिमान स्थापित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश की युवाशक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम से संभावनाओं को उपलब्धियों में बदल रही है। इसी ऊर्जावान युवाशक्ति के सामर्थ्य, सृजनशीलता और उपलब्धियों का अभिनंदन करने के लिए आज लखनऊ में आयोजित टीओआई यूथ आइकॉन्स समिट एवं अवार्ड्स 2026 में सहभागिता करूंगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को अवसरों के अभाव में पलायन करना पड़ता था। भर्तियों में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और अव्यवस्था से युवाओं का भविष्य अंधकारमय था। प्रतिभा थी, लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए अपेक्षित अवसर और प्रोत्साहन नहीं मिल पाता था।मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार ने इस कार्य-संस्कृति को बदला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने पारदर्शी भर्ती, कौशल विकास, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए आगे बढ़ने के नए अवसर सृजित किए हैं। आज उत्तर प्रदेश की युवाशक्ति केवल रोजगार की आकांक्षी नहीं, बल्कि रोजगार सृजन में भी अपनी नई पहचान गढ़ते हुए विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।



मंत्रिमंडल विस्तार से नेकां में असंतोष, उमर के सामने पार्टी एकजुट रखने की चुनौती

जम्मू (आससे.)। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल विस्तार ने नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के भीतर मंत्री पद की महत्वाकांक्षाओं और वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा का सवाल फिर खड़ा कर दिया है। चार नए मंत्रियों को शामिल करने और मौजूदा मंत्री सतीश शर्मा को हटाने के फैसले से सरकार का समीकरण बदला है, लेकिन पार्टी के सभी नेताओं को साथ लेकर चलना उमर के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्ला, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ कालू को जगह मिली है। वहीं, वरिष्ठ नेता मुबारक गुल को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने से निराशा की खबर सामने आई है। इससे पार्टी में वरिष्ठता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के करीबी नेताओं को प्राथमिकता दिए जाने को लेकर सवाल उठने की गुंजाइश बढ़ी है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही मंत्री पद के दावेदार विधायकों की संख्या और नेतृत्व पर दबाव की खबरें सामने आ रही थीं। उमर ने सार्वजनिक रूप से विधायकों से मंत्री पद के लिए उन्हें और पार्टी अध्यक्ष डा फारूक अब्दुल्ला को संदेश भेजना बंद करने की अपील की थी। यह संकेत था कि सीमित पदों के मुकाबले पार्टी के भीतर दावेदारों की संख्या कहीं अधिक है।

पूरा सिस्टम दवा निर्माताओं की कर रहा मदद-सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली (आससे)। सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) और रिटेलर को मिलने वाली कीमतों में भारी अंतर पर सरकार से सवाल किए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पूछा कि पूरा सिस्टम दवा निर्माताओं की मदद क्यों कर रहा है। कोर्ट ने नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को निष्क्रिय बताते हुए सवाल किया कि दवाओं की कीमतों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही। कोर्ट ने कहा कि सरकार की नजरों के सामने यह सब हो रहा है, क्या इसे ऐसे ही बेलगाम चलने देना चाहिए। दोनों मामलों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुद्दा ये है कि कई दवाओं की लागत 10-20 रुपए है, यह रिटेलर को 30 रुपए में मिलती है, पर एमआरपी 150-200 रुपए छपा होता है। यही गैप कोर्ट को खटक रहा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एंटी-कैंसर दवाओं का ट्रेड मार्जिन एमआरपी के 30 प्रतिशत तक सीमित करने पर केंद्र के जवाब को मुश्किल से कुछ खुश होने लायक बताया था।

कोर्ट ने सवाल किया था कि सरकार दूसरी दवाओं के ट्रेड मार्जिन की सीमा तय क्यों नहीं कर सकती। अस्पतालों के कैंसर दवाओं पर भारी मुनाफा जोड़े जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना का सामना कर चुके केंद्र ने कहा था कि उसने एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन स्ल्क्र के 30त तक सीमित करने का अहम फैसला लिया है। केंद्र के मुताबिक, इस फैसले से मरीजों को सालाना करीब 2,500 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया था कि ?2700 की कैंसर की दवा पर एमआरपी 27,000 क्यों है। कोर्ट ने दवाओं की कीमतों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह नरसंहार है।

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के शेयर अलॉटमेंट की प्रक्रिया हो रही पूरी

मुंबई-देश के सबसे बड़े प्राथमिक शेयर निर्गम जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ के अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब निवेशकों की नजरें इसके स्टॉक एक्सचेंज डेब्यू पर टिक गई हैं। 21 अक्तूबर से 23 अक्तूबर 2026 के दौरान बोली के लिए खुला 30,187.65 करोड़ रुपये का यह आईपीओ कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी ने अपने शेयर का कट-ऑफ प्राइस 1,119 रुपये प्रति शेयर तय किया है, जिसकी 28 अक्तूबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर लिस्टिंग होने जा रही है। ऐसे में जिन निवेशकों को अलॉटमेंट में शेयर हासिल नहीं हुए हैं, उनके लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे लिस्टिंग के दिन ही सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदें या कीमत स्थिर होने का इंतजार करें। जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के तीन आधिकारिक और पूरी तरह सुरक्षित तरीके हैं। आप इस आईपीओ के आधिकारिक रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजिस की वेबसाइट पर जाकर सीधे स्टेटस देख सकते हैं। इसके अलावा देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों- बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) के आधिकारिक आईपीओ अलॉटमेंट पोर्टल्स पर जाकर भी स्टेटस चेक किया जा सकता है। शेड्यूल के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट 26 अक्तूबर 2026 (सोमवार) से शुरू किया गया। आमतौर पर रजिस्ट्रार के पास डेटा प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लगता है, इसलिए अलॉटमेंट का फाइनल रिजल्ट 26-27 अक्तूबर की देर शाम या आधी रात तक आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन लाइव हो जाएगा। जियो आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस जांचने के लिए आप सीधे इन ऑफिशियल लिंक्स पर जा सकते है जिओ प्लेटफॉर्म्स का यह पब्लिक इश्यू भारतीय प्राथमिक बाजार का सबसे बड़ा आईपीओ रहा है, जिसके तहत 27 करोड़ नए शेयर जारी कर 30,187.65 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न निवेशक श्रेणियों में इस इश्यू को 22.19 गुना ओवरऑल सब्सक्रिप्शन मिला।जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में लिस्टिंग के दिन एंट्री लेने का फैसला पूरी तरह से शेयर के ओपनिंग प्राइस और शुरुआती सत्रों के ट्रेडिंग पैटर्न पर निर्भर करेगा। बाजार विशेषज्ञों की राय स्पष्ट है कि निवेशकों को ऊंचे भाव पर फोमो का शिकार होने के बजाय लिस्टिंग प्राइस के स्थिर होने या फिर आईपीओ प्राइस के समीप करेक्शन आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए।



कार्यालय अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड-3 खण्ड, लो.नि.वि.,गोरखपुर

निविदा आमंत्रण सूचना (ई-प्रोक्यूरमेंट सूचना)

पत्रांक-3767/1ए (निविदा) दिनांक 21-10-2026

महामहिम राज्यपाल, महोदय उत्तर प्रदेश की ओर से निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर में श्रेणी-'ए, बी, सी व डी' में रोड सेफ्टी कार्य हेतु पात्र पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में) जी0एस0टी0 सहित	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने का समय
1	2	3	4	5	6	7
1	गोरखपुर	जगदीशपुर पिपराईच मार्ग पर स्थित जगदीशपुर पिपराईच पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	34.50	3.45	(स्टेशनरी चार्जेज + निविदा मूल्य + जी.एस.टी.) रू0 856.00	02 माह वर्षा ऋतु सहित

बिड डाक्यूमेंट वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर दिनांक 02-11-2026 से 13-11-2026 तक उपलब्ध है, जो कि दिनांक 13-11-2026 को दोपहर 12:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। इसकी तकनीकी बिड दिनांक 13-11-2026 को दोपहर 12:30 बजे खोली जायेगी। निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि 13-11-2026 को 12:00 बजे तक शुद्धि पत्र यदि कोई हो तो उसे वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा।

निविदाओं की तकनीकी मूल्यांकन प्रहरी सापटवेयर के माध्यम से किया जाना है, जिसकी विस्तृत जानकारी बिड डाक्यूमेन्ट के साथ संलग्न निविदा सूचना में उपलब्ध है।

निविदा से सम्बन्धित अधिक जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

(यू.पी. सिंह)
अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड-3, लो.नि.वि.,
गोरखपुर

उ.प्र. 259516/दिनांक 26-10-2026 ईमेल-upinformation@nic.in

कार्यालय अधीक्षण अभियंता
गोरखपुर वृत्त, लो.नि.वि., गोरखपुर

पत्रांक-8165/33 काम-गोरखपुर वृत्त/2026 दिनांक 15-10-2026

ई-निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0 की ओर से उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के "ए व बी" श्रेणी के पात्र मार्ग कार्य हेतु पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, महराजगंज के अन्तर्गत नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	सिविल कार्य की लागत (रू0 लाख में)	5 वर्षीय अनुरक्षण की लागत (रू0 लाख में)	सिविल कार्य की लागत (रू0 लाख में) (4+5)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य समस्त कर सहित (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षा ऋतु सहित)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मार्गो का नव निर्माण कार्य।							
1	महराजगंज	कोल्हुई बृजमनगंज मार्ग से कोहार टोला होते हुए पसरखाड़ तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।(पाँच वर्ष का अनुरक्षण सहित)	167.00	4.20	171.20	10.56	(स्टेशनरी चार्जेज + निविदा मूल्य+ जी.एस.टी.) रू0 2714.00	6 माह	A,B
2		सैलदह कवलदह उर्फ कवलपुर से हबीबगढ़ त्रिलोकपुर से उखडहिया होते हुए कोइरौपुर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य। (पाँच वर्ष का अनुरक्षण सहित)	141.00	3.50	144.50	9.23	(स्टेशनरी चार्जेज + निविदा मूल्य+ जी.एस.टी.) रू0 2714.00	6 माह	A,B

बिड डाक्यूमेंट वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर दि0 02.11.2026 से 16.11.2026 तक उपलब्ध है, जो कि दिनांक 16.11.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। इसकी तकनीकी बिड दि0 16.11.2026 को अपरान्ह 12.30 बजे खोली जायेगी। निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि 16.11.2026 को 12:00 बजे तक शुद्धि पत्र यदि कोई हो तो उसे वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा।

निविदा से सम्बन्धित अधिक जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

(एडीसन)
अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
महराजगंज

(अशोक कुमार वर्मा)
अधीक्षण अभियंता
गोरखपुर वृत्त, लो.नि.वि.
गोरखपुर

उ.प्र. 259550/दिनांक 26-10-2026 ईमेल-upinformation@nic.in

कार्यालय अधीक्षण अभियंता
गोरखपुर वृत्त, लो.नि.वि., गोरखपुर

पत्रांक-8164/33 काम-गोरखपुर वृत्त/2026 दिनांक 15-10-2026

ई-निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0 की ओर से उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के "ए व बी" श्रेणी के पात्र मार्ग कार्य हेतु पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, महराजगंज के अन्तर्गत नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	सिविल कार्य की लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य समस्त कर सहित (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षा ऋतु सहित)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महराजगंज	तहसील-मुख्यालय नौतनवां के अन्तर्गत बहुउददेशीय हब मुडिला में 26X26 मी0 साईज के मानकीकृत हेलीपैड एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	171.00	10.55	(स्टेशनरी चार्जेज + निविदा मूल्य+ जी.एस.टी.) रू0 2714.00	10 माह	A,B

1. प्रत्येक निविदा की धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) ई-टेण्डर पोर्टल के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक निविदा का निविदा प्रपत्र शुल्क (नॉन रिफन्डेबल), ई-टेण्डर पोर्टल के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा।

बिड डाक्यूमेंट वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर दि0 02.11.2026 से 16.11.2026 तक उपलब्ध है, जो कि दिनांक 16.11.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। इसकी तकनीकी बिड दि0 16.11.2026 को अपरान्ह 12.30 बजे खोली जायेगी। निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि 16.11.2026 को 12:00 बजे तक शुद्धि पत्र यदि कोई हो तो उसे वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा।

निविदा से सम्बन्धित अधिक जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

(एडीसन)
अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
महराजगंज

(अशोक कुमार वर्मा)
अधीक्षण अभियंता
गोरखपुर वृत्त, लो.नि.वि.
गोरखपुर

उ.प्र. 259551/दिनांक 26-10-2026 ईमेल-upinformation@nic.in

कार्यालयः-नगर पंचायत सेवरही-कुशीनगर
सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि नगर पंचायत सेवरही, जनपद कुशीनगर कार्यालय के गृहकर पंजिका वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 के अन्तर्गत गृहकर पंजिका में अपना नाम दर्ज कराने हेतु निम्न व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। यदि किसी भी मकान से सम्बन्धित नामान्तरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति हो तो निम्नलिखित दिनांक के अन्दर अपने आपत्ति के समर्थन में साक्ष्य/सबूत के साथ नगर पंचायत सेवरही, जनपद कुशीनगर कार्यालय पर उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा नामान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी।

क्र.सं.	स्वामी का नाम	आवेदक का नाम	नामान्तरण का प्रकार	वार्ड का नाम	मकान सं.	आपत्ति का दिनांक
01.	03	04	05	02	06	07
01.	भोलानाथ शर्मा पुत्र बंका उर्फ बांकेलाल शर्मा	श्री अमरनाथ शर्मा व कैलाशनाथ शर्मा पुत्रगण स्व. भोलानाथ शर्मा व कंचन देवी पत्नी स्व. भोलानाथ शर्मा	वरासत	11 स्वर्णनगर 12 जवाहर नगर	129 133	29-11-2026

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत सेवरही-कुशीनगर

संख्या-मेमो/नामा./न.पं.से./2026-27/दिनांक 24-10-2026

कार्यालयः-नगर पंचायत सेवरही-कुशीनगर
सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि नगर पंचायत सेवरही, जनपद कुशीनगर कार्यालय के गृहकर पंजिका वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 के अन्तर्गत गृहकर पंजिका में अपना नाम दर्ज कराने हेतु निम्न व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। यदि किसी भी मकान से सम्बन्धित नामान्तरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति हो तो निम्नलिखित दिनांक के अन्दर अपने आपत्ति के समर्थन में साक्ष्य/सबूत के साथ नगर पंचायत सेवरही, जनपद कुशीनगर कार्यालय पर उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा नामान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी।

क्र.सं.	स्वामी का नाम	आवेदक का नाम	नामान्तरण का प्रकार	वार्ड का नाम	मकान सं.	आपत्ति का दिनांक
01.	03	04	05	02	06	07
01.	श्री द्वारिका प्रसाद पुत्र स्व. मोतीलाल प्रसाद रौनियार	सीमा रौनियार पुत्री द्वारा प्रसाद रौनियार	पंजीकृत बैनामा	02 जानकी नगर	90/168 वर्तमान म.सं.-199	29-11-2026

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत सेवरही-कुशीनगर

संख्या-मेमो/नामा./न.पं.से./2026-27/दिनांक 24-10-2026

कार्यालय-नगर पंचायत मेंहदावल, जनपद-संत कबीरनगर
ई-निविदा सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत मेंहदावल में मरम्मत/निर्माण कार्य हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई-प्रक्योरमेन्ट की बेवसाइड https: //etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। उक्त निविदा में नगर पंचायत मेंहदावल, संत कबीर नगर में अपंजीकृत/पंजीकृत ठेकेदार भी प्रतिभाग कर सकते है। सर्व न्यून निविदादाता होने पर नगर पंचायत मेंहदावल, संत कबीर नगर में पंजीकरण अर्हता पूर्ण कराकर नगर पंचायत मेंहदावल, संत कबीर नगर में पंजीयन कराना होगा। पंजीकरण की अर्